

पहलगाम में पर्यटकों की हत्या करने वाले तीनों आतंकवादी मारे गए

केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, तीनों लश्करे तैयबा के ए श्रेणी के आतंकवादी थे

नयी दिल्ली, 29 जुलाई। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में घोषणा की कि पहलगाम आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले तीनों आतंकवादी सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गये। शाह ने लोक सभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि ऑपरेशन महादेव के दौरान कल पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकवादी सुलेमान, अफगान और जिब्रान सैन्य बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गये। उन्होंने बताया कि सुलेमान आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा का ए श्रेणी आतंकवादी और तथाकथित कमांडर था। अफगान और जिब्रान भी लश्करे तैयबा से जुड़े हुए ए श्रेणी के आतंकवादी थे।

उन्होंने बताया कि मारे गये तीनों आतंकवादियों के पहलगाम घटना में शामिल होने की पुष्टि इन्हें पनाह देने वालों से करायी गयी है। पहलगाम हमले

में इस्तेमाल हथियारों से निकले खोखे की मिलान कर लिया गया है और इसकी पुष्टि हो गयी है कि इन आतंकवादियों के कब्जे से बरामद हथियार ही पहलगाम हमले में इस्तेमाल किये गये थे। शाह ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इन आतंकवादियों को पहलगाम घटना के बाद शरण और भोजन देने वालों को गिरफ्तार किया था। उनसे इन आतंकवादियों की पहचान करायी गयी है। इन आतंकवादियों के पास पाकिस्तान निर्मित चाकलेट बरामद की गयी थी।

उन्होंने कहा कि वह पहलगाम हमले में मारे गये पर्यटकों के पीड़ित परिजनों से कहना चाहते हैं कि

शाह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कहा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार हर आतंकी हमले का करारा जवाब देती है।

राष्ट्रपति आतंकवादी घटना को अंजाम देने वालों ने आतंकवादियों को सैन्य बलों ने सोमवार को मार गिराया है और पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं को ऑपरेशन सिन्दूर

के दौरान ही नेस्तनाबूद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि पहली बार भारत ने पाकिस्तान के 1०0 किलोमीटर अंदर स्थित आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। इससे पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ही आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया था।

शाह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान स्थित नौ आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने के अलावा पाकिस्तान के 11 एयरबेस क्षतिग्रस्त किये गये इनमें नौ तो पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान के छह राडार सिस्टम ध्वस्त किये गये। इस तरह पाकिस्तान के सेना के कमर तोड़ दी गयी तो उसके पास युद्ध विराम करने की गुहार लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की पूर्व में की गयी गलतियों के कारण ही पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2०14 से पहले आतंकवादी हमलों का पाकिस्तान को सटीक जवाब नहीं जाता था लेकिन अब मोदी सरकार हर आतंकवादी हमले का करारा जवाब देती है।

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 37० हटाये जाने के बाद कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी आयी है। पथराव की घटनायें बंद हो गयी है। वहां आतंकवादी इकोसिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। अब घाटी में बंद आहूत नहीं किये जाते।

‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास लगभग 3४,००० मामले लंबित’

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यन ने पत्रकारों को जानकारी दी

जस्टिस राममूर्ति ने हैदराबाद के डॉ.एम.सी.आर. मानव संसाधन विकास संस्थान में दो दिवसीय शिविर में शिरकत की।

जस्टिस राममूर्ति ने हैदराबाद के निपटारा किया जिनमें क्रमशः 36 और 51 मामले खंडपीठों द्वारा और 19 मामले पूर्ण पैनेल द्वारा निपटाए गए।
उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि आयोग ने हिरासत में हुई मौतों के मामलों में मुआवजे के आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें से अधिकांश भुगतान पहले ही किए जा चुके हैं और अन्य चार हफ्तों के भीतर होने की उम्मीद है।
आयोग ने हैदराबाद में शिविर के दौरान खंडपीठों और एक पूर्ण आयोग

श्रीनगर, 29 जुलाई। उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी) लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने मंगलवार को यहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन महादेव के बारे में जानकारी दी।

इस मौके पर उनके साथ 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव भी मौजूद थे।

आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उपराज्यपाल ने ऑपरेशन महादेव की सफलता के लिए सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि आतंकवादी घटनाओं के निपटारे में आतंकवादियों के छिपे होने की लगातार खबरें मिल रही थीं। हाल ही में विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर, विशेष टीमों को सक्रिय किया गया था। इसके बाद सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने खुफिया

कमांडिंग-इन-चीफ ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से दक्षिण कश्मीर के दार्चीगाम के जंगल क्षेत्रों में तलाशी अभियान जारी था। इस क्षेत्र में आतंकवादियों के छिपे होने की लगातार खबरें मिल रही थीं। हाल ही में विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर, विशेष टीमों को सक्रिय किया गया था। इसके बाद सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने खुफिया

कमांडिंग-इन-चीफ ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से दक्षिण कश्मीर के दार्चीगाम के जंगल क्षेत्रों में तलाशी अभियान जारी था। इस क्षेत्र में आतंकवादियों के छिपे होने की लगातार खबरें मिल रही थीं। हाल ही में विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर, विशेष टीमों को सक्रिय किया गया था। इसके बाद सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने खुफिया

कमांडिंग-इन-चीफ ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से दक्षिण कश्मीर के दार्चीगाम के जंगल क्षेत्रों में तलाशी अभियान जारी था। इस क्षेत्र में आतंकवादियों के छिपे होने की लगातार खबरें मिल रही थीं। हाल ही में विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर, विशेष टीमों को सक्रिय किया गया था। इसके बाद सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने खुफिया

क्षतिग्रस्त किये गये इनमें नौ तो पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान के छह राडार सिस्टम ध्वस्त किये गये। इस तरह पाकिस्तान के सेना के कमर तोड़ दी गयी तो उसके पास युद्ध विराम करने की गुहार लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की पूर्व में की गयी गलतियों के कारण ही पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2०14 से पहले आतंकवादी हमलों का पाकिस्तान को सटीक जवाब नहीं जाता था लेकिन अब मोदी सरकार हर आतंकवादी हमले का करारा जवाब देती है।

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 37० हटाये जाने के बाद कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी आयी है। पथराव की घटनायें बंद हो गयी है। वहां आतंकवादी इकोसिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। अब घाटी में बंद आहूत नहीं किये जाते।

मोदी ने चोल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अनाद्रमुक के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर संबंध बनाए हैं।

पहले यह धारणा थी कि भाजपा अनाद्रमुक पर दबाव बना रही है, लेकिन अब अनाद्रमुक कार्यकर्ताओं को भी लगाने लगा है कि यह साझेदारी स्वेच्छिक और सम्मानजनक हो सकती है।

मोदी की यात्रा के दौरान, अनाद्रमुक ने प्रधानमंत्री के तिरुच रोड शो को सफल बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को संगठित किया, जो यह संकेत देता है कि पार्टी अब भाजपा के साथ काम करने को लेकर अपनी पुरानी झिझक छोड़ चुकी है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले, प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भाजपा नेता कई बार तमिलनाडु का दौरा करेंगे। इन कार्यक्रमों में अनाद्रमुक कार्यकर्ताओं की भागीदारी दोनों पार्टियों के बीच विश्वास और समन्वय को और मजबूत कर सकती है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य भाजपा अध्यक्ष नैथनार नागेन्द्रन ने संकेत दिया है कि वह ईपीएस के अनाद्रमुक नेताओं को उनके राज्यव्यापी दौरे के दौरान भोजन पर आमंत्रित करेंगे, जो अगले महीने शुरू होने वाला है।

आयोग ने हैदराबाद में शिविर के दौरान खंडपीठों और एक पूर्ण आयोग

सुप्रीम कोर्ट बिहार की मतदाता सूची पर फिलहाल हस्तक्षेप नहीं करेगा

नयी दिल्ली, 29 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण में 65 लाख मतदाताओं के मतदाता सूची से बाहर होने की आशंकाओं पर मंगलवार को मौखिक रूप से फिर कहा कि यदि ऐसा हुआ तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा।

न्यायमूर्ति सूर्य कान्त और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण की आशंका पर यह आश्वासन दिया। पीठ के समक्ष अधिवक्ता भूषण ने निर्वाचन आयोग के इस बयान का

मतदाताओं को मतदाता सूचि से बाहर किये जाने पर कार्यवाही का आश्वासन।

जिऊ किया कि 65 लाख लोगों ने पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान गणना फॉर्म जमा नहीं किए हैं। भूषण ने कहा कि इससे उन मतदाताओं के मतदान के अधिकार से वंचित होने की आशंका है। शीर्ष अदालत बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर, सुनवाई 12 और 13 अगस्त को करने वाली है।

खड़गे पर नड्डा के बयान से राज्यसभा में बवाल मचा

बाद में नड्डा ने अपने शब्द वापस लिए और माफी मांगी

लेकिन नड्डा ने यह भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता को प्रधानमंत्री की गरिमा का ख्याल रखना चाहिये था।

तकलीफ समझ सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें 11 साल से विपक्ष में बिटाए रखा है। प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ये हमारे लिए भी और देश के लिए भी गौरव का विषय है। लेकिन आपकी चिंता पार्टी के लिए

इतनी है कि उसमें देश का विषय भी गौण हो जाता है। आप भाववेश में आकर ऐसी टिप्पणियां करते हैं। इसके बाद सदन में हंगामा हो गया और कांग्रेस सांसदों ने शर्यसदीय शब्द पर कड़ी आपत्ति जताई। इस पर नड्डा ने ये शब्द कार्यवाही से हटाने की अपील की। इससे सदन की कार्यवाही थोड़ी देर

‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास लगभग 3४,००० मामले लंबित’

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यन ने पत्रकारों को जानकारी दी

जस्टिस राममूर्ति ने हैदराबाद के डॉ.एम.सी.आर. मानव संसाधन विकास संस्थान में दो दिवसीय शिविर में शिरकत की।

सत्र के माध्यम से 87 मामलों का निपटारा किया जिनमें क्रमशः 36 और 51 मामले खंडपीठों द्वारा और 19 मामले पूर्ण पैनेल द्वारा निपटाए गए। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि आयोग ने हिरासत में हुई मौतों के मामलों में मुआवजे के आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें से अधिकांश भुगतान पहले ही किए जा चुके हैं और अन्य चार हफ्तों के भीतर होने की उम्मीद है।

न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने कहा "तेलंगाना में हमारे पास केवल 780 मामले लंबित हैं। इनमें पुलिस हिरासत में हुई मौतों के चार मामले और न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के 30 मामले शामिल हैं।"

न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने मौडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा "हम समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखते हैं। जब भी हमें हिरासत में मौत, खुले नालों में गिरने से मौत, स्कूलों या छात्रावासों में लापरवाही के कारण आत्महत्या जैसी घटनाओं का पता चलता है, हम कार्रवाई करते हैं। मौडिया हमें समाज को नज़र पढ़ ने में मदद करता है।"

उन्होंने कुछ हालिया मामलों का हवाला दिया जिनमें एक किशोर को गलत तरीके से 4० दिनों की जेल हुई थी। इस बाबत उसे मुआवजा दिया गया । इसी प्रकार स्कूलों में बड़े पैमाने पर खाद्य विषाक्तता के मामले शामिल हैं जिनकी जाँच की जा रही है।

अध्यक्ष ने एक उल्लेखनीय हस्तक्षेप का भी उल्लेख किया जहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार से अपहृत एक लड़की का पता लगाने और उसे बचाने में मदद की। वह राजस्थान में मिली थी और सीमा पार मानव तस्करी के लिए भेजी जाने वाली थी।

वैश्विक मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग पर न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यन ने इस रैंकिंग में असमानताओं को स्वीकार करते हुए कहा कि आयोग नीति कार्यान्वयन में सुधार के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है।

उन्होंने कहा "हम यहाँ केवल बोलने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ सुनने के लिए हैं। मौडिया की, कार्यकर्ताओं की और अधिकारों के उल्लंघन का सामना करने वालों की हम सुनेंगे। यह सहयोग वास्तविक बदलाव की कुंजी है।"

दिल्ली-एनसीआर में अगले सात दिन भारी बारिश की आशंका

मौसम विभाग ने रैंड अलर्ट जारी किया

नयी दिल्ली, 29 जुलाई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और अन्य राज्यों में अगले सात दिनों में बारिश होने का अनुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में आज मूसलाधार बारिश होने के बाद रैंड अलर्ट जारी कर दिया। राजधानी समेत पूरे एनसीआर में आज सुबह से तेज बारिश होने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज पूरे दिन बारिश रुक-
दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को भी तेज बारिश हुई, जिससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ।
रुक बारिश होने का अनुमान जताया था, जब सुबह शुरू हुई तेज बारिश के कारण आईटीओ, धोला कुआं, नारायणा, पटेल नगर, विजय चौक, जंगपुरा, आर के पुरम, लाजपत नगर, तालकटोरा रोड, रफी मार्ग, वजीरपुर, भजनपुरा और रोहिणी

नयी दिल्ली, 29 जुलाई। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और अन्य राज्यों में अगले सात दिनों में बारिश होने का अनुमान जताया है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में आज मूसलाधार बारिश होने के बाद रैंड अलर्ट जारी कर दिया। राजधानी समेत पूरे एनसीआर में आज सुबह से तेज बारिश होने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज पूरे दिन बारिश रुक-

नयी दिल्ली, 29 जुलाई। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दरअसल, खड़गे की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर कही गई बातों पर नड्डा ने आपत्ति जताई और कुछ ऐसा बोल गए कि विपक्ष ने हंगामा कर दिया। इसके बाद नड्डा ने अपने शब्द वापस ले लिए। अगर मेरी बात से किसी का दिल दुखा तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन खड़गे जी जैसे वरिष्ठ नेता ने देश के प्रधानमंत्री के लिए जैसी बातों का इस्तेमाल किया है, वो ठीक नहीं है।

दरअसल, राज्यसभा में खड़गे के बयान पर कुछ आपत्तियों के साथ जेपी नड्डा ने बोलना शुरू किया। नड्डा ने कहा कि विपक्ष के नेता ने लंबा वक्तव्य दिया, लेकिन उनके कद के हिसाब से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो उनके स्तर के नहीं थे, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की। मैं उनकी

नयी दिल्ली, 29 जुलाई। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दरअसल, खड़गे की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर कही गई बातों पर नड्डा ने आपत्ति जताई और कुछ ऐसा बोल गए कि विपक्ष ने हंगामा कर दिया। इसके बाद नड्डा ने अपने शब्द वापस ले लिए। अगर मेरी बात से किसी का दिल दुखा तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन खड़गे जी जैसे वरिष्ठ नेता ने देश के प्रधानमंत्री के लिए जैसी बातों का इस्तेमाल किया है, वो ठीक नहीं है।

दरअसल, राज्यसभा में खड़गे के बयान पर कुछ आपत्तियों के साथ जेपी नड्डा ने बोलना शुरू किया। नड्डा ने कहा कि विपक्ष के नेता ने लंबा वक्तव्य दिया, लेकिन उनके कद के हिसाब से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो उनके स्तर के नहीं थे, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की। मैं उनकी

के लिए बाधित हुई। खरगे ने बयान को लेकर नड्डा से माफी की मांग की। इस पर नड्डा ने कहा कि आपको अगर ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन आप भी भाववेश में इतना बह गए कि प्रधानमंत्री की गरिमा का भी ध्यान नहीं रख पाए।

ट्रंप ने रूस को 10-12 दिन का नया अल्टीमेटम दिया

लंदन, 29 जुलाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने यूक्रेन युद्धविराम पर सहमत होने के लिए रूस को "1० या 12 दिन" की एक नयी, छोटी समय सीमा दी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेन्स्की ने इस अवधि को "बेहद महत्वपूर्ण" बताया है।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अब और इंतज़ार करने का "कोई कारण" नहीं है, क्योंकि शांति की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। विदित हो कि दो सप्ताह पहले ट्रम्प ने कहा था कि राष्ट्रपति पुतिन के पास युद्ध समाप्त करने के लिए 5० दिन है, अन्यथा रूस को कड़े आयात शुल्कों का सामना करना पड़ेगा।

रूस ने कहा, ट्रंप के अल्टीमेटम मॉस्को में काम नहीं करते।

कल स्कॉटलैंड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक के बाद प्रसारित से बात करते हुए, ट्रम्प ने यूक्रेन में चल रही गतिविधियों पर फिर से अपनी असहमति जताते हुए कहा कि उन्हें "अब बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है"। सोमवार के ताजा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए रूसी सांसद अद्वैद गुरुखोव ने कहा है कि ट्रम्प के अल्टीमेटम "अब काम नहीं कर रहे..न अग्रिम मोर्चे पर, न मॉस्को में" और रूस के पास "हथियारों, सिद्धांतों और इच्छाशक्ति" की ताकत है।

विदित हो कि शांति के लिए रूस ने शांति के लिए जो शर्तें रखी हैं वे यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों को अस्वीकार्य हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स , राष्ट्रदूत भवन, चूंंगी नका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65०15/96, जयपुर कार्यालय: सुघर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 41०3333-34 फैक्स : ०141-2३73513, कोटा कार्यालय : एचयूएफ हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386०31, 2386०32,फैक्स:०7४4-०294-241०146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाउस, हनुमान हत्या, बीकानेरा फोन: 220०66०, फैक्स ०151-2527371, जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालोरा फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डोन्सिटी कार्यालय** :- जी -1-2०1, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डोन्सिटी। फोन: 23०200, 23०400, फैक्स: ०7469-23०6०० **चूरू कार्यालय** : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 2569०6, 2569०7, फैक्स: ०1562-2569०8

